हेल्थ सिस्टम को भी डीसैन्ट्रलाइज़ करने की बात की है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि अपोलो हॉस्पीटल्स ग्रुप जो है, उनका जो नेशनल रूरल हेल्थ केयर मॉडल है जिसके बहुत सारे बैनिफिट्स भी हैं और खास तौर पर लो कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंशोरेंस भी है, तो क्या यह पूरे देश में लागू किया जा सकता है ?

SHRI A. RAJA : At present, we are having no proposal for medical insurance.

Demand of tobacco growers of Andhra Pradesh

*605. DR. ALLADI P. RAJKUMAR : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether a delegation of tobacco growers of Andhra Pradesh met him on 12th March, 2003 and requested Government to come forward to help the growers who are in a hopeless condition;

(b) if so, the main demands raised by the delegation; and

(c) Government's response to their demands?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. The main demands of the delegation are as below :

(i) Permit the Tobacco Board to undertake market intervention operations during the current marketing season.

(ii) Creat an exclusive Price Stabilization Fund for FCV tobacco.

(iii) The Tobacco Board must continue to regulate crop production and fix the individual crop quotas. The Peer Review Committee recommendations in this regard should be overlooked.

(iv) Tobacco Board may be given plan assistance of Rs. 54.50 crores during the 10th Plan.

(v) Foreign Direct Investment should be allowed in tobacco sector and foreign merchants should be allowed to participate in the auctions directly to create competition in the market.

(c) The Board is required to intervene in the market when prices of Flue Cured Virginia (FCV) Tobacco fall below the Minimum Support Price (MSP). At Present, the prices prevailing in the ongoing tobacco auctions in Andhra Pradesh are above the MSP. The Government, after due consideration, has already constituted a Price Stabilization Fund for tobacco growers alongwith some other plantation crops. The Board has been provided with a plan assistance of Rs. 2 crores. As regards 'Peer Review', the process of consulting the concerned State Governments on the recommendations made in the Report has been taken in hand. Under extant Industrial Policy, investment in cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes are subject to compulsory licensing.

डा० अलादी पी० राजकुमार : सर, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है और मंत्री महोदय बहुत इंटेलीजेंट हैं। . . . (**व्यवधान**) सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तारीख 12 मार्च को आन्ध्र प्रदेश से काफी टोबैको फॉर्मर्ज़ आए और उन्होंने आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया और उस रिप्रेजेंटेशन में पांच अंशों पर उन्होंने मंत्री जी को जल्द से जल्द नज़र डालने और उस पर एक डिसिज़न देने के लिए पूछा है। उन पांच अंशों पर अभी तक उन्होंने क्या निर्णय लिया, इस पर मैं मंत्री महोदय का जवाब चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली : सभापति जी, आंध्र प्रदेश के कुछ टोबेको प्लांटेशन ग्रोअर्स और कुछ सांसद 12 मार्च को मुझ से मिले थे और आंध्र प्रदेश में टोबेको ग्रोअर्स की समस्या से मुझे अवगत कराया था। उस सारी स्थिति का आंकलन हम लोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से और टोबेको बोर्ड के माध्यम से भी कर रहे हैं। सभापति जी, उनकी एक मांग यह थी कि गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवेंशन करे। उनकी एक और प्रमुख मांग यह थी कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार किसी कोप के संबंध में घोषणा करे। इसके अतिरिक्त एक पियर रिव्यू कमेटी की जो रिकमंडेशंस आई है, उन में सुझाव यह था कि अभी मार्केट को डि-रेगुलराइज करने की आवश्यकता नहीं है। महोदय, सरकार ने इन सब विषयों का अध्ययन किया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार प्लांटेशन ग्रोअर्स की वह समस्या न रहे। सरकार ने टोबेको और अन्य प्लांटेशन ग्रोअर्स के लिए 500 करोड़ रुपए का एक प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड बनाया है जिस के तहत हर प्लांटेशन के संबंध में एक प्राइस बैंड तय होगा और अगर कीमत उस से नीचे जाती है तो उस फंड से उस प्लांटेशन ग्रोअर्स को कुछ धनराशि दी जाएगी जिस से उन की सहायता की जा सके।

महोदय, जहां तक मार्केट इंटरवेंशन का सवाल है, टोबेको बोर्ड इस सिद्धांत पर काम करता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है, अगर उस से कम कीमत चली जाए तो मार्केट इंटरवेंशन हम लोग करते हैं। महोदय, अभी जो प्रति दिन टोबेको की ऑक्शंस हो रही हैं, कर्नाटक में संपन्न हो चुकी हैं और आंध्र प्रदेश में चल रही हैं, उसके ऊपर हम डेली बेसिस पर नजर रखते

हैं कि उस की ऑक्शन प्राइस क्या हैं और उसमें इस स्टेज पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है या नहीं। जहां तक पियर रिव्यु कमेटी का संबंध है, इस में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों से विपरीत प्रकार के सुझाव आए हैं। पियर रिव्यु कमेटी ने कहा था कि डि-रेगुलेशन करने के लिए मार्केट को एडजस्ट होने के लिए तीन वर्ष की अवधि दी जाए। आंध्र प्रदेश का सुझाव यह है कि इस को बिल्कुल भी अभी डि-रेगुलेशन करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। कर्नाटक का यह सुझाव है कि इस को तुरंत डि-रेगुलेट करना चाहिए। इन सब सुझावों को लेने के बाद सरकार उन का अध्ययन कर रही है और इस बारे में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

MR. CHAIRMAN : You must be satisfied with this question also.

डा० अलादी पी० राजकुमार : नहीं सर, अभी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर, प्रश्न के भाग "सी" के जवाब में दिया गया है "At present, the prices prevailing on ongoing tobacco auction in Andhra Pradesh are above Minimum Support Price." यह बात सही नहीं है। This is not a fact. Recently, just last week, I, myself went to West Godavari District, that is, Gopalapuram Constituency, where in an area of 40,000 acres of tobacco has been grown by the farmers. Sir. I have seen with my own eyes that farmers are still holding the tobacco in their houses because of not getting the Minimum Support Price. सर, मेहरबानी कर के आप डायरेक्शन दीजिए। Andhra Pradesh is one of the leading tobacco-producing States in the country, apart from Karnataka. Sir, Managing Director of Karnataka Tobacco Board is adopting a biased attitude in respect of Karnataka and Andhra Pradesh. Sir, for this purpose, even my Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu, has also written a letter to Commerce Minister, So, kindly see to this. *(Interruptions)* . . . .

श्री सभापति : आप का क्वैश्चन हो गया, अब उन्हें बोलने दीजिए।

डा० अलादी पी० राजकुमार : सर, आप का डायरेक्शन चाहिए। अब सत्र खत्म हो रहा है। . .(**व्यवधान**) . . . उन्हें एक बार जाकर टोबेको ग्रोअर्स . . .(**व्यवधान**) . . . सर, आप भी एक फार्मर हैं . . .(**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं चलूंगा।

डा० अलादी पी० राजकुमार : सर, आप खास तौर से डायरेक्शन दीजिए।

श्री सभापति : मैं देता हूं, आप मुझे ले चलिए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा, डेली बेसिस पर हम लोग उस की कीमत का अध्ययन करते हैं। इस वक्त जो मेन कैटेगरीज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वह 28 और 30 रुपए किलो ग्राम का है। महोदय, पिछले वर्ष आंध्र

प्रदेश में जो एवरेज सेल हुई थी, कर्नाटक की सेल संपन्न हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में अभी चल रही है, आंध प्रदेश की सेल का एवरेज प्राइस 39 प्लस 97 था। महोदय, परसों 2 मई तक आंध्र प्रदेश में जो सेल अभी तक हुई हैं, उस का एवरेज प्राइस 42.21 रु० पर किलो ग्राम है। इसलिए थोड़ी-सी बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक देखी गई है, लेकिन किसी स्टेज पर अगर यह कम होती है तो उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं, उस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगभग रेगुलर बेसिस पर हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। जहां तक वहां आने का प्रश्न है, मैं या मेरे सहयोगी विद्यासागर राव जी जो आंध्र प्रदेश से ही हैं, हम लोग स्थिति से संपर्क बनाए हुए हैं और आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम वहां आकर उस स्थान पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे।

*606 [The questioner (Suri Raj Kumar Dhoot) was absent. for answer *vide* page, —36-37]infra.

Facilities to unregistered tobacco growers of Karnataka

*607. SHRI K. RAHMAN KHAN : Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have agreed recently to consider the demand for extending facilities for crop loans, fertilizers, pesticides, etc. to the unregistered tobacco growers of Karnataka and for giving more representation to Karnataka tobacco growers on the Tobacco Board; and

(b) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

SHRI K. RAHMAN KHAN : Sir, in reply to parts (a) and (b) of my question, the hon. Minister has replied, " 'No, Sir' and 'Does not arise' ". I would like to know from the Hon. Minister as to whether the small growers, the unregistered small growers, of tobacco from Karnataka have made a demand for providing crop loans, pesticides, etc. If so, even though the reply of the Minister is that the Government has not agreed to any such demand, I would like to know whether the Government is going to consider these demands of the small growers.

SHRI ARUN JAITLEY : Sir, as far as the issue pertaining to Karnataka is concerned, the principle question related to composition of the Tobacco Board. Now, as far as the demands that are being made are concerned, these demands